राज्य कर्मियों को जल्द मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

10 साल बाद किसी सीएम ने कर्मचारी प्रतिनिधियों से की वार्ता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी व अन्य। अमर उजाला

लखनऊ। राज्य कर्मचारियों को जल्द इलाज की कैशलेस सुविधा मिलेगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के शिष्टमंडल के साथ वार्ता के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मांग पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग समेत तमाम मुद्दों पर लंबी वार्ता हुई। करीब 10 साल बाद किसी मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों के शिष्टमंडल से अधिकृत तौर पर वार्ता की।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी की अगुवाई में एक शिष्टमंडल बुधवार को मुख्यमंत्री से मिला। इसमें परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव, विशिष्ट बीटीसी संगठन के अध्यक्ष संतोष तिवारी और परिषद नेता संजीव गुप्ता शामिल थे। बाद में तिवारी ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं की फील्ड स्टाफ को मोटर साइकिल भत्ता और जबरन सेवानिवृत्ति से संबंधित मांग पर सकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब काम सरकारी है तो मोटर साइकिल भत्ता भी मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 50 साल से ऊपर दी जा रही जबरन सेवानिवृत्ति में छोटे नहीं बल्कि बड़े अधिकारियों पर नजर है। इस भेंट में कैशलेस इलाज के लिए अभियान चलाकर हेल्थ कार्ड बनवाने, उच्च तकनीकी क्षमता वाले अस्पतालों के साथ समझौता करने, आउटसोर्सिंग व संविदा व्यवस्था समाप्त कर सीधी भर्ती करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, विभागीय विवाद प्रतितोष फोरम को सक्रिय करने आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलास्तर, विभाग और शासन स्तर पर नियमित बैठकों के लिए जरूरी निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया। राजकीय कर्मचारियों की तरह बेसिक शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा देने, उनकी पदोन्नति में ठहराव और स्थानांतरण पर भी चर्चा हुई। राजस्व विभाग के लेखपालों को लैपटॉप व स्मार्टफोन देने के लिए कैबिनेट बैठक में निर्णय करने का आश्वासन भी दिया गया। ब्यूरो